डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-904 **New Delhi: 05.01.2021**

श्री राकेश कुमार शर्मा
पुत्र श्री हरदयाल शर्मा
मकान न0-19/213, गली न0-06
हनुमान पुरी , महेंद्र नगर, पोस्ट-गंम्भीरपुरा, तहसील-कोल
जनपद-अलीगढ़
उत्तर प्रदेश-200201

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 10.12.2020, इस कार्यालय में दिनांक 16.12.2020 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आरo पीo छिब्बर
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 07 पृष्ठ

05.01.2021

(एस. के. राय)
उप. महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
011-23454707

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A) **दिनांक:- 04.01.2021**

Dy.GM/Admin/PIO

डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- I आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2020/HQ/ADMIN/RTI-904 दिनांक 17.12.2020 मुख्य महा प्रबन्धक/टूंडला कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 17.12.2020.

II उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़ के पत्र दिनांक 01.01.2021.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I के तहत श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़, का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला को सूचित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़ द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है

04/01/21

(सुभाष चंद्रा)
महाप्रबन्धक/विधुत/टूंडला

संलग्नक:- 06 प्रष्ठ.

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित |

Office Of Chief Project Manager- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower Mayur Complex Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02, Agra -282002
Telefax: 0562-2885577 E mail,abkhare@dfcc.co.in. Mob: 7660803006
Website www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेषन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)/Amended

दिनांकः- 01.01.2021

महाप्रबन्धक/विधुत

डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

टूंडला,

विषयः- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः- । मुख्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2020/HQ/ADMIN/RTI-904 दिनांक 17.12.2020.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के तहत श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री हरदयाल शर्मा, निवासी- म. न. 19/213, गली न. 6, हनुमानपुरी महेन्द्र नगर जनपद- अलीगढ़, का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी आपको निम्नलिखित उपलब्ध करायी जा रही है ।

क्र. सं.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत किसानो की जमीन पर 132 के०वी० (डबल सर्किट) ट्रांसमिशन लाईन के टावर फाउन्डेशन निर्माण आदि के अंतर्गत कृषको/भू-स्वामियों को क्षति हुई उनकी फसलो एवं प्रभावित हुई उनकी जमीन की क्षतिपूर्ति हेतु आपकी परियोजना को क्या क्या दिशा निर्देश जारी किये गए है एवं आपके द्वारा प्रभावित कृषको/भू-स्वामियों को उनकी क्षति हुई फसलो एवं प्रभावित हुई जमीन के एवज में किस तरह लाभान्वित किया गया है कि स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परियोजना के अंतर्गत किसानो की जमीन पर 132 के०वी० (डबल सर्किट) ट्रांसमिशन लाईन के टावर फाउन्डेशन निर्माण आदि के अंतर्गत कृषको/भू-स्वामियों को उनकी क्षति हुई फसलो एवं प्रभावित हुई जमीन के एवज में "टेन्डर नं०–एच/ईएल/132 के०वी०टी०आर०एल क्रॉसिंग/ई०सी०–02" के **पार्ट–II, चैप्टर–VIII** के पैरा सं०–2.8.8 के **III(b), VI** के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।
2	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं कार्यरत संस्था मै. एसोसिएटेड पॉवर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टावर फाउन्डेशन संख्या 73/1 के निर्माण हेतु दिए गए प्रथम सुचना नोटिस की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	132 के० वी० डबल सर्किट नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के 132 के० वी० पुरानी पारेषण लाइन के डी.एफ.सी.सीआई.एल. के परिक्षेत्र के विस्थापन हेतु टावर फाउन्डेशन 73/1 का प्रथम सूचना नोटिस मै. एसोसिएटेड पॉवर स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रार्थी को देने का प्रस्ताव किया गया था, परन्तु

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,Mayur Complex,Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02,Agra -282002
Telefax: 0562-2885577 E mail,abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

Scanned with CamScanner

		प्रार्थी ने पत्र लेने से इनकार कर दिया था । प्रार्थी ने मा० न्यायलय से डी.एफ.सी.सी.आई.एल. के कार्यो के विरुध स्टे लेने के किये केस दायर किया गया था। परन्तु मा० न्यायलय ने स्टे देने से मना कर दिया था ।
3	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल परियोजना द्वारा टावर फाउन्डेशन निर्माण के समय आपके अधिकार क्षेत्र अलीगढ़ एवं हाथरस के प्रभावित किसानो की विंदुवार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	यह सूचना आपको सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 8.1. (घ) के तहत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है ।

01/01/2021

(अंशुल राजपूत)

(उप परियोजना प्रबन्धक/विधुत/अलीगढ़)

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,Mayur Complex,Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02,Agra -282002
Telefax: 0562-2885577 E mail,abkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

Scanned with CamScanner

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Tender No. HQ/EL/132KV TRL- XING/EC-02

For

Design, supply, erection, testing and commissioning of 132 KV, 3 phase double circuits Transmission Line Crossing Modification work for DFC alignment in Allahabad Division of North Central Railway

Employer:
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE
Under
MINISTRY OF RAILWAYS

00000040

Scanned with CamScanner

PART II

CHAPTER VIII

2.8 ERECTION OF THE TRANSMISSION LINE

PARA NO.	SUBJECT
2.8.1	Scope
2.8.2	Compliance with regulations.
2.8.3	Inspection
2.8.4	Measurements
2.8.5	Foundations
2.8.6	Towers
2.8.7	Stringing of conductors and ground wire.
2.8.8	Way-leave and site clearance.

Scanned with CamScanner

any, for each, such tree/property to DFCCIL for submitting to the owner. The contractor will be required to co-ordinate/liaison with owner for obtaining such clearances/permission on behalf of DFCCIL. However, if any compensation is to be paid to the concerned State/Central/Forest department, the same shall be paid directly by the employer. The tree cutting/trimming of such identified trees will have to be done by the contractor, who shall hand over such cut trees/crops to employer/owner (as decided) at the same location.

iii) (b) Damage to private trees/crops/property.

Where cutting/damage to any tree/crops/property belonging to private party becomes necessary for construction of transmission line, the contractor will have to directly negotiate with the concerned party for way leave and pay all compensations. The tree cutting/trimming and all related activities will be done by the contractor. The disposal of such trees/crops/damaged property shall be responsibility of the contractor.

iv) It shall be the responsibility of contractor to ensure that required clearances as per relevant clauses IS:5613 (latest edition) are available.

v) During the process of erection, if any obstruction is encountered from the villagers/outsider/any other Govt./Semi Govt./Private agency, the contractor shall resolve the same at his own cost.

vi) No compensation whatsoever (i.e. idle charges, rate escalation, loss or profit or any other losses) will be granted to the contractor on ground of non availability of right of way including approval from the Railway, P&T Deptt., Forest Deptt. and consequent delays. Further non availability of right of way alone will not become a sufficient ground for extension of completion period unless contractor proves that all formalities at his end have been completed and he has made all efforts timely for securing right of way.

The compensation for trees, crops etc. (except government forest), if required to be paid to execute erection of the line and for getting clearance as per relevant clause of IS:5613 (Pt.II/Sec.2) - 1976 shall be reimbursed by the Employer supported by the receipt in original granted by the owner of the trees/crops and duly certified by BDO/SDO or Engineer-in-charge and any local authorities (Govt.).

The rate for compensation for trees which may be required to be felled down as indicated above will be paid as per prevalent rate of the concerned DFO. However, the rate for crop compensation will be paid as per the rate fixed by the local BDO/SDO or local Govt. authorities. However, the felling down of above trees/crops etc. is the responsibility of Contractor and has to be done by him at his own cost for which no extra payment will be made. The Contractor

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lX7qwkkd6iOlhKRGZTm_mDc6YXLC7dDR
Scanned with CamScanner

shall take all responsible steps to minimise damage to standing crops as far as practicable.

In event of any Govt. Forest unavoidably falling along the route alignment, negotiation with Forest Department of State Govt. will be done by DFCCIL and if any compensation is to be paid for getting the requisite clearance, it is to be paid by DFCCIL directly to the Forest Department. Felling down of the trees will be done by the Contractor at his own cost. Contractor shall hand over such cut trees to employer/owner (as decided) at the same location.

vii) If any claim from any private/Govt. party for damage to tree/crop/property, right of way, way leaves, access to sites, etc. arises against DFCCIL during erection of transmission line or even later after construction upto a period of 18 months after issue of PAC, the same shall be simply passed over to the contractor for disposal. The contractor shall be responsible for settling the issue as per law and assuring that DFCCIL is not put to any in convenience.

However, if due to any statutory rules/regulations/obligations, court ruling, the DFCCIL is required to make any payment to anybody (other than a Govt. department) the same shall have to be reimbursed by the contractor within 30 days of making such a claim (date of issue).

In event of non-payment of same by the contractor within 30 days of date of issue of such a claim, the employer may take action to recover the amount from any Securities/guarantees/payments of the contractor available with employer. This is without prejudice to other remedies available to the employer under the law.

xxxxxx

Scanned with CamScanner